केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 116 मंगलवार 19 नवम्बर 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार

नई दिल्ली (आभा)। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भगोड़े भाई अनमोल बिश्नोई को सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अनमोल, जो एक खूंखार गैंगस्टर भी है और भारत में कई हाई–प्रोफाइल हत्या के मामलों में वांछित था, को पहले ही दिन कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया था। अनमोल बिश्नोई पिछले साल भारत से भाग गया था, अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद बिश्नोई गिरोह द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क में एक प्रमुख नाम बन गया। अनमोल भारत में

कई आपराधिक मामलों में वांछित है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना और 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है।

वह इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हाल ही में हुई हत्या में भी शामिल हैं। अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस अपराध शाखा इकाई द्वारा उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ सप्ताह बाद अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। अनमोल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज दो मामले और 18 अन्य आपराधिक मामले भी हैं। हाल ही में आतंकी जांच एजेंसी ने उस व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की जो अनमोल बिशोई के बारे में जानकारी देगा जिससे उसकी गिरफ्तारी होगी।

थमा चुनाव प्रचार 20 को मतदान 23 को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली (आभा)। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया। झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों के लिए वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,086 स्वतंत्र दावेदार हैं। हालाँकि, इस बार, पिछले दो वर्षों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग होने से राजनीतिक परिदृश्य अधिक

खंडित है।

लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुईं यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार भी अब खत्म हो गया है। दो दिन दिन यानी 20 नवंबर को सभी नौ विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे।

सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में से, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 149 उम्मीदवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 81 उम्मीदवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। विपक्षी महा विकास अघाड़ी में, कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के 95 उम्मीदवार और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के 86 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और कई केंद्रीय मंत्रियों जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने के लिए राज्य भर में प्रचार किया।

झारखंड में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की अधिसंख्य सीटें संथाल और कोयलांचल क्षेत्रों में स्थित हैं। इस चरण में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहने वाली है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रबींन्द्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह, बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू, तनाव बरकरार

नई दिल्ली (आभा)। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सुरक्षा बलों और राज्य की एजेंसियों से शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। शाह ने राज्य में सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी हैं।

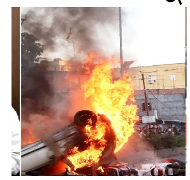

इस बीच केन्द्र सरकार मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती भी बढा रही है और वहां केन्द्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। इससे पहले भी केन्द्र ने वहां 20 कंपनियां तैनात की थी।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ अन्य क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। हिंसा की घटनाओं के बाद उग्र भीड़ ने कुछ विधायक को और मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ तथा आगजनी भी की है जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

प्रदूषण का कहर, दिल्ली– एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश

नई दिल्ली (आभा)। प्रदूषण के बेकाबू स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली–एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर की सरकारों से इस पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराने का आदेश दिया गया है। इन दो क्लासेज को छोड़कर राजधानी में बाकी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को 12वीं कक्षा तक सभी क्लासों को ऑफलाइन मोड में कराने से तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए।

अदालत ने प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए सख्त उपायों को लागू करने में हुई देरी के चलते

एक टीम गठित करने को कहा है। यह टीम ग्रैप–4 के प्रतिबंधों को लागू करेगी जो कि एक्यूआई 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेगी। न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करें। पीठ ने कहा कि हम ग्रैप–4 के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, भले ही एक्यूआई लेवल 450 से नीचे आ जाए।शुरुआत में पीठ ने ग्रैप चरणों के तहत प्लूशन रोकथाम के उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया था। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।दिल्ली एनसीआर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 1000 के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए राजधानी में ग्रैप–4 लागू करने का आदेश दिया गया था और अब 10वीं और 12वीं के स्कूली बच्चों की कक्षाएँ भी ऑनलाइन करने का आदेश आ गया है।

एक नजर

सीएमओ के निरीक्षण में सामने आया जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का सच

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले में पीएचसी पर लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का सीएमओ डॉ. आरएस दूबे ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पीएचसी पर चाक चौबंद व्यवस्था दिखी तो कई पर खामियां मिली। उन्होंने लैब के उपकरणों से लेकर अन्य सुविधाएं और मरीजों की स्थिति की जांच की। स्वास्थ्य मेलों की हकीकत परखने के लिए सीएमओ डॉ. आरएस दूबे पीएचसी बानपुर का निरीक्षण किया। 14 मरीज देखे गए थे, जिसमें तीन की जांच हुई थी। डॉ. मनोज पांडेय 14 मरीज देख चुके थे। वहीं होम्योपैथिक डॉ. अजय गुप्ता अनुपस्थित रहे। उनका वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों की जांचों से लेकर अन्य सुविधाएं देखी। नगरीय पीएचसी नहरिया और बरदहिया में भी मेला लगा। यहां मरीजों की जांच हुई। सर्दी–जुकाम और बुखार के रोगी अधिक थे। अन्य पीएचसी पर एलोपैथ के डॉक्टर कम दिखे। आयुष और फार्मासिस्ट ही उपचार किए। पीएचसी बेलघाट में 38 मरीज आए जिनका इलाज एवं परामर्श डॉ. प्रेमचंद ने दिया। फार्मासिस्ट राजेश कुमार सिंह ने दवा बांटी। पीएचसी मुसहा में एलोपैथ के बजाय आयुष चिकित्सक डॉ. नफीस खान ने 37 मरीज देखे। फार्मासिस्ट राम सुरेश वर्मा ने दवा बांटी। पीएचसी न्यू हलुआ बाजार में 35 मरीज आए। डॉक्टर नहीं थे तो फार्मासिस्ट रामतौल जायसवाल और संविदा फार्मासिस्ट बीआर प्रजापति ने जांच कर दवाएं दी। वार्ड ब्वाय रवीश मणि त्रिपाठी, एलटी विनय शुक्ल ने सहयोग किया। भानपुर संवाद के अनुसार पीएचसी परसाकुतुब में मेला लगा। डॉक्टर नहीं थे तो फार्मासिस्ट संजय कुमार ने जांच की। 30 मरीज देखे गए। पीएचसी करमहिया में एलोपैथ के बजाय आयुष चिकित्सक डॉ. अमिष कुमार ने जांच की। यहां 41 मरीज आए।

नहीं है गेहूं का बीज, किसान परेशान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विकास खंड कुदरहा परिसर में स्थापित राजकीय कृषि बीज भंडार पर पिछले एक सप्ताह से गेहूं के बीज की आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि गेहूं का बीज नहीं मिलने से बुआई नहीं हो पा रही है।

गोदाम प्रभारी क्षितिज वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष 580 कुंतल गेहूं बीज बंटा था। इस बार 680 कुंतल गेहूं का वितरण हो चुका है। लक्ष्य से अधिक वितरण होने के कारण कुछ समस्या आ रही है। शनिवार तक गेहूं का बीज आने की संभावना है।

मासूम शिष्या से अश्लील हरकत मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मासूम शिष्या से कक्षा में अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पैकोलिया थाने की पुलिस को दिया है। घटना गौर ब्लॉक क्षेत्र के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हुई। अदालत ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक सप्ताह में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि अदालत का आदेश मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। पीड़िता की मां ने अदालत में दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी नाबालिग बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा है। आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक उसकी बेटी से अकेले कमरे में पानी लेकर आने को कहता है। वहां जाने पर वह उसके साथ अश्लील हरकत करता है। उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करता है। घटना के डर के कारण वह विद्यालय नहीं गई। बहुत पूछने पर उसने पूरी घटना परिवार को बताई। बेटी का कहना था कि गुरुजी ने धमकी दी है कि अगर घर पर किसी से बताओगी तो तुम्हारे पिता की हत्या कर देंगे।

टोल प्लाजा पर मनमानी रोकने की मांग: सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। एपीएन पीजी कालेज के पूर्व छात्रसंघ महामंत्री शीतला सिंह ने सोमवार को जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय सड़क, परिवहन राज मार्ग मंत्री नीतिन गड़करी को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि जनपद में हर्रैया तहसील क्षेत्र के चौकड़ी एवं बस्ती बड़े बन में स्थित टोल प्लाजा से मनमाने ढंग से ऑन लाइन गाडी के नम्बर से एक्टिव फास्ट ट्रैक से धनराशि काट लिये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय।

ज्ञापन देने के बाद शीतला सिंह ने बताया कि जनपद का यह दुर्भाग्य है कि 30 किलोमीटर की दूरी पर जनपद में दो टोल प्लाजा हर्रैया तहसील क्षेत्र के चौकड़ी एवं बस्ती बड़े बन में सक्रिय है। एक टोल प्लाजा को हटाने के लिये लम्बा संघर्ष किया गया किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। जनपद के स्थानीय नम्बरों वाले वाहनों को हर्रैया तहसील क्षेत्र के चौकड़ी एवं बस्ती बड़े बन में स्थित टोल प्लाजा से पहले तो जाने दिया जाता है किन्तु कुछ देर बाद जिन वाहनों में फास्ट ट्रैक एक्टिव हैं उनसे मनमाने ढंग से धनराशि की कटौती कर लिया जाता है। यह खुले आम नियमों के विरूद्ध है किन्तु टोल प्लाजा संचालकों/ कम्पनियों द्वारा लगातार यह खेल जारी है। यही नहीं विरोध करने पर अनेक गाडी स्वामियों, चालकों से टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी दुर्व्यवहार भी करते हैं। मांग किया कि समूचे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कराने के साथ ही ठगी पर रोक लगवाया जाय। चेतावनी दिया कि यदि प्रभावी कार्रवाई न हुई तो बाध्य होकर आन्दोलन किया जायेगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में अंकुर सिंह, हर्षित त्रिपाठी, मनोज यादव, आदित्य यादव, दिवाकर कुमार, शिवजी, दीनू पाल, शानू यादव, जितेन्द्र यादव, लाल कुमार, अभिषेक सिंह, अतुल सिंह, आशीष राय, श्याम विश्वकर्मा, संध्या श्रीवास्तव दया कुमार आदि शामिल रहे।

एपीएन पीजी कालेज में छात्र समस्याओं के समाधान के लिये दिया धरना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। एपीएन पीजी कॉलेज में साफ सफाई व स्कॉलरशिप फॉरवर्डिंग न किये जाने को लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुधीर और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी सहित कांग्रेस नेताओं, छात्रों ने छात्र नेता सुनील चौधरी के संयोजन में महाविद्यालय परिसर में धरना दिया। मांग किया कि परिसर में साफ–सफाई के साथ ही कक्षाओं को नियमित संचालित कराये जाने के साथ ही स्कॉलरशिप फॉरवर्डिंग कराया जाय।

कांग्रेस नेता एवं एनएसयू प्रभारी नोमान अहमद ने छात्रों के धरने का समर्थन करते हुये कहा कि एपीएन पीजी कॉलेज बस्ती मण्डल का महत्वपूर्ण महाविद्यालय है। इसके परिसर गंदे हों, शराब की बोतले मिले यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक हैं। जब नियमित कक्षायें ही नहीं चल पा रही है तो स्कॉलरशिप

–महाविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बने–नोमान

फॉरवर्डिंग के लिये 75 प्रतिशत का मानक बना लिया जाना चिन्ताजनक हैं। उन्होने कहा कि अच्छा हो कि प्राचार्य समस्याओं को समझें और समस्याओं का निस्तारण करायें। अन्यथा की स्थिति में संघर्ष को और तेज किया जायेगा।

युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुधीर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी, छात्र नेता सुनील चौधरी आदि ने कहा कि महाविद्यालय का पठन पाठन सुधारने के साथ ही स्कॉलरशिप फॉरवर्डिंग कराया जाय। धरने में अर्पित पाठक, रामकेश यादव , सोनम सैनी के साथ ही एपीएन पीजी कॉलेज के अनेक छात्र शामिल रहे।

डीएम ने देखा धान क्रय केन्द्र का सच

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने धान क्रय केंद्र साऊघाट केंद्र विपणन विभाग द्वारा संचालित मंडीयार्ड तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 बायपोखर ओडवारा का औचक निरीक्षण किया। केंद्र विपणन विभाग द्वारा संचालित मंडीयार्ड के निरीक्षण में उन्होने पाया कि केंद्र पर भंडारण स्थल, तौल यंत्र, नमी मापक यंत्र, पावर डस्टर उपलब्ध हैं तथा सही से कार्य कर रहा हैं। वहॉ पर उन्होने सैम्पल की नमी चेक कराकर देखा, तो 15 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 17 प्रतिशत के मानक के अंदर आयी।

उन्होने निरीक्षण में पाया कि केंद्र पर तौल प्रारम्भ है। वहॉ पर

उपस्थित कृषक नागेश्वरनाथ ने बताया कि धान विक्रय करने में कोई समस्या नहीं आ रही है। पूर्व में भी उनके द्वारा धान विक्रय किया गया था। उन्होने बताया कि भुगतान के विषय मे मेरा अंगूठा लगा है। क्रय केंद्र प्रभारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कल तक इनका भुगतान हो जायेगा। केन्द्र पर अभी तक कुल 12 कृषकों से 608 क्विन्टल धान क्रय किया गया है तथा उनमे से 11 कृषको को रू. 1412418 का भुगतान भी किया गया है।

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 बायपोखर ओडवारा के निरीक्षण में उन्होने पाया कि केंद्र पर डीएपी उर्वरक उपलब्ध हैं एवं वितरण कार्य चल रहा है। पीओएस मशीन के संचालन में संचालक ने समस्या बताया। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को सही करवाने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

नवाचारी शिक्षण विधियां, गणित किट के लिए 439 शिक्षक प्रशिक्षित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे नवाचारी शिक्षण विधियां एवं गणित किट प्रशिक्षण के दूसरे बैच का समापन सोमवार को हुआ। दोनों बैचों में जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 439 गणित शिक्षक प्रशिक्षित किए गए। प्रशिक्षण समापन अवसर पर डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण निश्चित रूप से गणित विषय को रोचक ढंग से पढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे बच्चे गणित किट के बारे में बारीकी से सीख सकेंगे। सभी शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी हुई विधाओं को अपनी कक्षाओं में लागू करें ताकि इस प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध हो सके। नोडल प्रवक्ता अलाउद्दीन ने कहा कि शत प्रतिशत विद्यालयों में गणित किट के प्रयोग के साथ ही नवाचारी शिक्षण विधियां अपनाई जाएं ताकि बच्चों को विषय वस्तु रोचक लगे। संदर्भदाता

–रोचक ढंग से पढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा प्रशिक्षण– संजय शुक्ल

हरेंद्र कुमार यादव, डॉ अनूप सिंह, बालमुकुंद और अमरेंद्र चौधरी द्वारा प्रतिभागियों को विषय वस्तु की जानकारी के साथ ही विभिन्न प्रकार की नवाचारी शिक्षण विधियां और गणित किट प्रयोग के तरीके बताए गए। जिसमें बीजगणित की अवधारणा, बीजीय व्यंजन, संक्रियाएं, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, समीकरण एवं सर्वसमिका की समझ, नवीन अवधारणाएं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आदि को विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से बताया गया। कार्यक्रम में डॉ गोविंद प्रसाद, डॉ रविनाथ त्रिपाठी, मो. इमरान आदि उपस्थित रहे।

डीबीटी में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने बच्चों की डीबीटी में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनके प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया जटिल होने से जिले के परिषदीय विद्यालयों के दस हजार बच्चो से अधिक सरकार द्वारा भेजी जाने वाली स्कूल ड्रेस,स्वेटर,जूता मोजा और बैग की डीबीटी राशि से वंचित है। जिसके चलते इस ठंड के मौसम में स्वेटर ना होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक अभियान चलाकर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था को सरल किया जाए। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने कहा कि जिन बच्चों का आधार बना भी है और अभिभावकों का आधार बैंक में फीड नही है तो उनका डीबीटी नहीं हो पा रहा है क्योंकि डीबीटी के लिए आधार कार्ड का सीड होना जरूरी है। अतः इस मामले में बैंकों को निर्देशित जाए कि बच्चों के अभिभावकों का बैंक खाता आधार से लिंक करके

-बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, आधार बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए- चन्द्रिका सिंह

उसे सीड अवश्य करें। ताकि डीबीटी योजना से वंचित बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव और जिला उपाध्यक्ष रवीश कुमार मिश्र ने कहा कि बच्चों के पास आधार न होने से प्रधानाध्यापकों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आधार के लिए ऊपर से विभागीय दबाव बनाया जाता है। आधार बनवाने की जटिल प्रक्रिया के चलते आधार विहीन बच्चों का नामांकन मजबूरन खारिज भी करना पड़ता है। विद्यालयों में नामांकन कम होने का कारण भी आधार ही है। साथ ही बच्चों के पास आधार न होने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी, शिव प्रकाश सिंह, प्रवीन श्रीवास्तव,संगठन मंत्री अविनाश दुबे, विवेक कान्त पाण्डेय, ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र यादव,सनद पटेल,सुरेश गौड़, अखिलेश पाण्डेय, रविप्रताप सिंह,अशोक यादव,रामसागर वर्मा,रंजन सिंह,अनिल पाठक, मंत्री रामभवन, दिनेश सिंह,संजय चौधरी,रामपियारे कन्नौजिया, संजय यादव, विजय यादव, राहुल सिंह, सुनील, प्रशांत बरगाह, विवेक सिंह, मुरलीधर, संजय यादव, आशीष दुबे, सुरेन्दर यादव,पवन यादव आदि शामिल रहे।

“मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 19 नवम्बर 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

बढ़ते सड़क हादसे

कोहरा शुरू होते ही सड़क दुर्घटनायें और बढ जाती हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली सड़कें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आए दिन होने वाले सड़क हादसे सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की ओर से वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी एक रपट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष दस लाख पैंतीस हजार से अधिक मौतें होती हैं और पांच करोड़ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। रपट के अनुसार, विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौत में से 11 फीसद भारत में होती हैं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2018 में आधिकारिक तौर पर करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। रपट कहती है कि विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर 23 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है।भारत में सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन केवल सड़कों को विस्तृत करने तक सीमित है, जिसके कारण कई बार सड़कों और राजमार्गों पर श्ब्लैक स्पाटश बन जाते हैं। ये वह स्थान होते हैं, जहां सड़क दुर्घटना की संभावना सबसे अधिक रहती है। सड़क हादसों के कारण होने वाली 80 फीसद मौत के लिए वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

भारत की सड़कों पर चलना अब जान हथेली में रखकर चलने जैसा ही होता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली—चंडीगढ़ हाईवे पर पानीपत के निकट रॉन्ग साइड से आए एक ट्रक ने पांच लोगों की जान ले ली। बताया जाता है कि ड्राइवर नशे में था। रास्ते में जो आया उसे कुचलता चला गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसी दुर्घटनाओं में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। वे लोग जो अपने परिवारों के भरण—पोषण के संघर्ष में जुटे रहते हैं। जिनके लिये यह जीवनभर का दुख बन जाता है। वहीं कई घायल जीवनभर के लिये विकलांगता झेलने को अभिशप्त हो जाते हैं। कमोबेश सारे देश में ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं जिनमें रोज सैकड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देश की इन कातिल सड़कों की हकीकत बताता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का एक डराने वाला आंकड़ा पिछले दिनों सामने आया। मंत्रालय के अनुसार पिछले दस सालों में हुए सड़क हादसों में 15 लाख लोग मारे गए। यह आंकड़ा भयावह है और इस गंभीरता को संबोधित करने की जरूरत बताता है। दरअसल, वर्ष 2014 से 2023 के बीच सड़क हादसों में 15.3 लाख लोग मारे गए। बताते हैं कि सड़क हादसों में मरने वाले लोगों में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। यह हमारी व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर कर रहा है कि क्यों हर साल डेढ़ लाख लोग मारे जा रहे हैं।

सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर भारत की सड़कों पर चलना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा क्यों होता जा रहा है? आखिर दस साल में केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ जैसे शहर की आबादी से ज्यादा लोग क्यों अकारण मौत के मुंह में चले जाते हैं? आखिर उन लोगों का क्या कसूर था कि उनके हिस्से में ऐसी दर्दनाक मौत आई? आखिर क्यों हम पूरी दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मरने वाले देश के रूप में जाने जाते हैं? ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि देश में हर दस हजार किलोमीटर पर मरने वालों की दर 250 है जबकि अमेरिका, चीन और आस्ट्रेलिया में यह संख्या 57, 119 व 11 है। निश्चित रूप से भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का यह आंकड़ा एक संवेदनशील व्यक्ति को हिलाकर रख देता है। हालांकि, देश में समय के साथ वाहनों की संख्या और सड़क निर्माण में भी वृद्धि हुई है, लेकिन दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। वर्ष 2012 में करीब 16 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड थी जो पिछले एक दशक में दुगनी हो गई हैं। लेकिन उस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ीं। जहां वर्ष 2012 में देश में भारतीय सड़कों की लंबाई 48.6 लाख किलोमीटर थी, तो वर्ष 2019 में यह 63.3 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची थी। यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा के तमाम उपायों के बावजूद देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है। इसके लिये ट्रैफिक व सामान्य पुलिस को सतर्क करने तथा यात्रियों को जागरूक करने की भी जरूरत है।

मादक पदार्थों का बढता कारोबार

—डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी—

बीती 25 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान गृह मंत्री ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा। स्मगलर नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर बढ़ रहे हैं। यह ड्रग्स कम मात्रा में आती है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। शाह ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जब देश की आजादी का 100 वां वर्ष मनाया जाएगा। धीरे—धीरे यह संकल्प 130 करोड़ आबादी का संकल्प बन गया है। मेरा मानना है कि नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृध्द, सुरक्षित और गौरवशाली भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है।''

जिस तरह से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश में फैल रहे ड्रग नेटवर्क का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। दिल्ली में दो हजार करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी वाकई चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की है। इस तस्करी से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है।

देश की राजधानी में इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना चौंकाने से अधिक चिंता की बात है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग—अलग हिस्सों में हर साल हजारों करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में इन पदार्थों की खपत होती है और युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। पाकिस्तान के रास्ते होने वाली इस तस्करी के जरिए समाजकंटक खूब पैसा कमा रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मिलीभगत का खेल भी चल रहा है।

अहम सवाल यह है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद नशे का यह जाल दिन दूनी, रात चौगुनी प्रगति कैसे कर रहा है? क्या पुलिस और सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत भी है? एक दशक पहले तक पंजाब को नशीले पदार्थों का केंद्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग पूरा देश इसकी गिरफ्त में नजर आ रहा है। तमाम सरकारी प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। क्या नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि सरकार उसके सामने कमजोर नजर आ रही है? या फिर हमारे कानून में कमी है जिससे अपराधियों को सजा ही नहीं मिल पाती? कई देशों में नशीले पदार्थों को लेकर सरकारें कड़े कानून बना रही हैं।

भारत मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी संबंधी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में 2020 में जब्त की गई अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा 5.2 टन है और उसी वर्ष जब्त की गई मॉर्फिन की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा 0.7 टन थी। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, भारत ने 2019 में विश्व भर में 7 फीसदी अफीम तथा 2 फीसदी हेरोइन को जब्त की।

भारत दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों— गोल्डन क्रिसेंट (ईरान—अफगानिस्तान— पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड—लाओस—म्यांमार) के बीच स्थित है, जो इसे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिये संवेदनशील बनाता है। भारत में व्यापक रूप से उत्पादित और उपयोग किये जाने वाले दो ड्रग्स अफीम और भांग हैं। पोस्ता के पौधे से अफीम और भांग के पौधे से भांग प्राप्त होती है। दोनों को साइकोएक्टिव ड्रग्स कहा जाता है, जिनके प्रयोग से लत और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार ने अवैध फसलों को नष्ट करने, ड्रग्स को जब्त करने, तस्करों को गिरफ्तार करने और जागरूकता उत्पन्न करने जैसे विभिन्न उपायों के साथ ड्रग्स पर कार्रवाई तीव्र कर दी है।

खबरों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की दो बड़ी जेलों में बंद 50 फीसदी कैदी नशा तस्करी के हैं। इसमें युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने मिशन क्लीन चला रखा है। इसके तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि वर्तमान में जिले की दो जेल चिट्टा समेत अन्य नशों की तस्करी के मामले में पकड़े कैदियों से भर गई हैं। इसमें प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों के तस्कर शामिल हैं।

कैथू जेल में वर्तमान में करीब 280 विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदी हैं। इसमें चिट्टा समेत अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े कैदियों की संख्या 133 है, यानि करीब 50 फीसदी हैं। इसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय कारागार कंडा में सजायाफ्ता और विचाराधीन दोनों तरह के कैदियों को रखा जाता है। इसमें करीब 500 कैदी हैं। पुलिस के मुताबिक इसमें से स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) एक्ट के मामलों में गिरफ्तार कैदियों की संख्या 165 है। इसमें 120 कैदी सजायाफ्ता हैं जबकि 45 विचाराधीन हैं। केंद्रीय कारागार में भी सबसे अधिक कैदी नशा तस्करी से जुड़े मामलों के हैं। नशा तस्करों की इस संख्या को लेकर हर कोई हैरान हैं।

चिट्टे समेत अन्य नशों की लत लगने के बाद युवा इसकी तस्करी के अवैध कारोबार से जुड़ जाते हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें 20 से 35 साल के युवाओं की संख्या अधिक है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नशा तस्करी में कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा किशोर भी नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। गिरफ्तार युवाओं से पूछताछ में पता चला है कि पहले वह नशे के आदी थे और जब उनके परिजनों को इसका पता चला तो उन्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इसके बाद नशा तस्करों ने उन्हें नशे के एवज में इसकी तस्करी करने के लिए मजबूर किया।

युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले ऐसे कृत्य से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के लिए भारत में भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है। अलग—अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय की भी जरूरत है। साथ ही आम जनता का सहयोग भी लिया जाना चाहिए, ताकि नशे के नेटवर्क का समय रहते पता चल सके और उसे तोड़ा जा सके।

कठोर और सख्त कानूनों के उपरांत भी नशीले पदार्थों का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है भ्रष्ट प्रशासन। पुलिस विभाग की निष्क्रियता, अपराधियों को शह और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है। पुलिस विभाग में इच्छाशक्ति हो तो महज कुछ दिनों मे पूरे भारत में नशे की तस्करी बंद हो सकती है।

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना जरूरी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नुक्कड़ नाटकों, पर्चों, बैनर—पोस्टर के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सभी कार्यालयों में गुटखा, तम्बाकू या अन्य प्रकार का नशा करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमों की समीक्षा भी होनी चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए लोगों को कितनी सजा मिली और अगर नहीं मिल पाई तो क्यों? अगर कानूनी दांवपेच के चलते किसी को सजा नहीं मिल पाई तो इसके लिए आखिर किसे दोषी माना जाए? तस्करों से सांठगांठ के चक्रव्यूह को तोड़ने में आ रही अड़चनों को दूर किए बिना अपेक्षित परिणाम की उम्मीद करना बेमानी होगा।

—चिकित्सक एवं लेखक

बीमार होती नदियां और तंत्र

—योगेन्द्र योगी—

हिन्दू शास्त्रों में गंगा और यमुना नदी का धार्मिक महत्व बताया गया है। इन नदियों की उपयोगिता के कारण इन्हें जीवनदायिनी कहा गया है। वर्तमान में हालत यह है कि ये जीवनदायिनी खुद जीवन के लिए तरस रही हैं। देश में अन्य समस्याओं की तरह इन नदियों के की बर्बादी के लिए भी राजनीति जिम्मेदार है। नदियों का प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक दलों को वोट नहीं दिला सकता, इसलिए इनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। सत्तारुढ़ दलों की प्राथमिकता में नदियों की पवित्रता बरकरार रखना नहीं रह गया है। इन नदियों की हालत नालों जैसी बन चुकी है। भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस हालत से निपटने के लिए सरकारी प्रयास विफल साबित हुए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हाईकोट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद नदियों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अदालतों ने नदियों में प्रदूषण के लिए कई बार भारी जुर्माना लगाया है। चुंकि जुर्माना नेता—अफसरों की जेब से नहीं जाता, इसलिए उसका ऊंट के मुंह में जीरे जितना ही असर हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी को अनुपचारित अवशिष्ट से प्रदूषित करने के लिए आगरा नगर निगम को 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी और यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर नगर निगम को फटकार लगाई। इस तरह के मामले में इससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने भी नगर निगम के खिलाफ अप्रैल में आदेश दिया था। यह पहला मौका नहीं है कि जब एनजीटी या अदालत ने नदियों के प्रदूषण के लिए सरकारी एजेंसियों पर जुर्माना लगाया हो, इससे पहले भी ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं, किन्तु शासन—प्रशासन की मिलीभगत से नदियों में प्रदूषण का स्तर का बढ़ता जा रहा है। हालात यह हो गए हैं कि नदियों का जल पीने लायक तो दूर आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है।

दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी कभी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। अब प्रदूषण के कहर से जूझ रही है। आंकड़े बताते हैं कि यमुना का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। छठ जैसे पर्व पर महिलाओं को इस नदी पर स्नान करने से रोक लगाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, यमुना में खतरनाक बैक्टीरिया और प्रदूषकों का स्तर मानक सीमा से कई गुना अधिक पाया गया है। दिल्ली में यमुना के प्रमुख हिस्सों में पानी की गुणवत्ता, बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) और अन्य प्रदूषक तत्वों के कारण न केवल पीने के योग्य नहीं है। यमुना में प्रतिदिन लगभग 3,000 मिलियन गैलन से अधिक सीवेज प्रवाहित होता है। यह बिना किसी सफाई प्रक्रिया के सीधे नदी में जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ यानी एक अरब रुपये और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया थ। इसी तरह बिहार सरकार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा नहीं कर पाने को लेकर राज्य सरकार पर चार हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2023 को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें महाराष्ट्र को अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर कई चेतावनियों के बावजूद राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राजस्थान सरकार पर लगाए 3000 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी। एनजीटी ने राजस्थान में गीले और सूखे कचरे के समुचित प्रबंधन में नाकाम रहने से पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर यह जुर्माना लगाया था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट ऑफ एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट 2023 में यह खुलासा किया कि देश के 30 राज्यों में कुल 279 (46 फीसदी) नदियां प्रदूषित हैं, हालांकि, 2018 के मुकाबले मामूली सुधार 2022 में देखा गया है। 2018 में 31 राज्यों में 323 नदियां प्रदूषित थीं। एसओई रिपोर्ट के मुताबिक देश की 279 अथवा 46 फीसदी प्रदूषित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र (55) में हैं जबकि इसके बाद मध्य प्रदेश में 19 नदियां प्रदूषित हैं वहीं, बिहार में 18 और केरल में18 नदियां प्रदूषित हैं। उत्तर प्रदेश में 17 और कर्नाटक में 17 नदियां जबकि राजस्थान में 14 और गुजरात में 13, मणिपुर में 13, पश्चिम बंगाल में 13 नदियां प्रदूषित हैं। देश की सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा के जल को घरों में रखा जाता था। अब हालत यह है कि गंगा नदी दो साल में 10 गुना मैली चुकी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 जगहों से गंगा जल की जांच की गई। नदी के पानी में प्रदुषण का बुरा हाल देखने को मिला। प्लास्टिक की थैलियों, दूध की पॉलीथीन, नदी के किनारे शवों का जलाना, गंगा नदी को लगातार प्रदूषित कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 स्थानों पर गंगा जल की जांच में यह भयावह तस्वीर सामने आई थी।

13 फरवरी 2023 को केंद्रीय जल शक्ति (जल संसाधन) राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने संसद को बताया था कि नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने में कारगर रही है। उन्होंने कहा था कि 2014 से केंद्र ने नदी की सफाई के लिए 32,912.40 करोड़ रुपये के बजट के साथ 409 परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गंगा नदी के पूरे भाग के 71 प्रतिशत क्षेत्र में कोलीफॉर्म के खतरनाक स्तर पाए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कोलीफॉर्म का स्तर सात स्टेशनों पर सबसे ज्यादा था। एनजीटी ने राज्यों से सीवेज ट्रिटमेंट पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसी की पालना में दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्वीकार किया गया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले 1,340 नालों में से 895 (66.8 प्रतिशत) बिना किसी सिवेज ट्रिटमेंट के सीधा गंगा को दुषित कर रहे हैं। वर्तमान में भी हालात में ज्यादा सुधार नहीं है। वर्ष 2018—2019 में गंगा द्वारा ले जाए गए प्लास्टिक कचरे की का आकलन किया गया। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के गंगा नदी अभियान में ये पाया गया कि गंगा नदी का प्लास्टिक का कचरा बड़े पैमाने पर सुमद्र में मिल रहा है।

देर से न्याय मिलने की विडम्बना

—उमेश चतुर्वेदी—

उलेमा बनाम उत्तरी दिल्ली मामले पर सुनवाई के दौरान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थीं, इस मामले पर आए फैसले का अंदेशा उनसे हो गया था। सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए मानक प्रक्रिया बनाकर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथ जरूर बांध दिए हैं। जैसा कि हर फैसले के साथ होता है, हर पक्ष अपने—अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोधी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं इसके समर्थक इस फैसले में भी कार्रवाई के लिए राह खोज रहे हैं। इससे साफ है कि बुलडोजर न्याय सिर्फ स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेक नहीं बन पाएगा। स्पीड ब्रेकर तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार को धीमी करता है, जबकि ब्रेक गाड़ी को रोक देता है। यह फैसला भी कुछ इसी तरह का साबित होने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को नियंत्रित करते वक्त एक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहां आपराधिक मामलों की सुनवाई की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस तरह की देर लगती है, उसे अपराध करने वालों ने अपने लिए आड़ बना रखा है। बरसों तक धीमी गति से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का एक संदेश यह है कि ताकतवर चाहे तो अपराध करने के बावजूद प्रक्रिया की घुमावदार गलियों में न्यायिक फैसले को टाल सकता है। यह टालना इतना लंबा हो जाता है कि एक तरह से वह न्याय से इनकार हो जाता है। देर है पर अंधेर नहीं की सोच भी उबाऊ और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के सामने धुंधली होते—होते समाप्त हो जाती है। इसी घुमावदार और लंबी—धीमी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प बनकर बुलडोजर न्याय उभरा था। राज्य सरकारों ने इसे त्वरित न्याय के साधन के तौर पर अपनाया और देखत ही देखते अपराधमुक्त समाज की चाहत रखने वालों की चहेती बन बैठीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की मानक प्रक्रिया बनाते हुए त्वरित न्याय के विकल्प या न्यायिक प्रक्रिया की घुमावदार गलियों को पूरी तरह नजरंदाज किया है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद अपराधियों, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों के उभार को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग सशंकित हो उठा है। देश की सबसे बड़ी अदालत होने के चलते सुप्रीम कोर्ट को इस सामाजिक सोच का भी संज्ञान लेना चाहिए और उसे भी आश्वस्त करना चाहिए कि उसके फैसले के बावजूद किसी गैंगस्टर, कोई अपराधी या समाज विरोधी तत्व को कमजोर तबके की जमीनों या सार्वजनिक संपत्तियों के अतिक्रमण का हक नहीं मिल जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तरी दिल्ली के एक मामले में दिया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीर पुरी में रामनवमी के दिन निकले जुलूस पर एक मस्जिद और उस इलाके से जुलूस पर हुए पथराव और उससे उपजी हिंसा के जवाब में दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई को सांप्रदायिक कार्रवाई का रंग देते हुए सेकुलर धारा के दिग्गज वकीलों मसलन कपिल सिब्बल आदि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भले ही सुनवाई इसी मामले की होती रही, लेकिन संदेश ऐसा गया मानो उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इसकी वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित न्याय के विकल्प के रूप में इसे अपनाया। तब उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर यह छवि बनाई गई कि वह सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम तबकों के खिलाफ ही बुलडोजर कार्रवाई करती है। जबकि योगी सरकार ने बिरादरी से ब्राह्मण लेकिन कर्म से माफिया और गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ भी इस कार्रवाई को किया। भदोही के बिरादरी से पंडित गैंगस्टर और राजनेता विजय मिश्रा की अतिक्रमित संपत्तियां भी उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर रहीं। लेकिन प्रचारित सिर्फ अतीक, मुख्तार जैसे मुस्लिम दबंगों और माफियाओं की संपत्तियों के खिलाफ हुई कार्रवाई ही की जाती रहीं। इस बहाने त्वरित न्याय के इस सरकारी विकल्प को हिंदुत्ववादी राजनीतिक दर्शन का ना सिर्फ नतीजा बताया गया, बल्कि यह नैरेटिव स्थापित कर दिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आम लोगों के बीच संदेश यही गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आया फैसला है।

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रचारित सिर्फ योगी सरकार रही, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि सरकारों ने भी की है। एक आंकड़े के मुताबिक, पिछले सात सालों में करीब 2000 अवैध अतिक्रमण बुलडोजर कार्रवाई में ढहाए गए। जिनमें सबसे ज्यादा करीब डेढ़ हजार मामले उत्तर प्रदेश के ही रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई से खाली कराई गई जमीनों को कमजोर तबकों में बांटा भी गया है। करीब सात सौ ऐसे प्लॉट बांटे जा चुके हैं। इसकी चर्चा कम हो रही है।

निश्चित तौर पर इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि किसी अपराधी के अपराध की कीमत उसका पूरा परिवार अपना घर गवांकर क्यों चुकाए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी का घर भी अगर सरकारी तंत्र के निशाने पर बना तो उसकी वजह उसका नियमित निर्माण नहीं, बल्कि अवैध कब्जा और अतिक्रमण रहा। अब तक बुलडोजर कार्रवाई नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे में स्थानीय जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जिला अधिकारी की निगरानी में होगी और इसके लिए मान्य प्रक्रिया और नोटिस आदि देने की अवधि का पूरी तरह निर्वहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की राह में एक बाधा नजर आ रही है। जिला प्रशासन समय और काम के बोझ का बहाना बनाकर ऐसी कार्रवाइयों को टाल सकता है। अपराधी, माफिया और गैंगस्टर कब्जे करते रहेंगे, और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के चलते वे अपने अपराध को प्रकारांतर से स्थापित करते रहेंगे।

स्वस्थ गांव व समाज से ही होता है स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण -राकेश

संवाददाता–बलरामपुर। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सोमवार को एमपीपी इंटर कालेज में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता डॉ राकेश श्रीवास्तव रहे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ ग्राम व स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। निरोगी काया के लिए हर व्यक्ति को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। योग गुरू डॉ वीरेन्द्र विक्रम सिंह ने योगिक क्रियाओं से शरीर शुद्धि की बात कही। कहा कि आईएनओ एवं सूर्या फाउंडेशन की ओर से तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में एक महा अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है।

विशाल सिंह हत्याकांडः करणी सेना ने दिया अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर पैर नहीं- सिर में मारें गोली

संवाददाता–देवरिया। विशाल हत्याकांड कांड के मामले में करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू सोमवार को मृतक के परिवार से मिलने उनके गांव हौली बलिया पहुंचे। पूरे दलबल के साथ हौली पहुंचे वीरू सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। इससे पहले मृतक विशाल सिंह की मां व पिता से भी मिले। वीरू सिंह ने पुलिस को 48 घंटे में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का समय दिया।

उन्होंने कहा कि देवरिया पुलिस के नकारेपन के कारण क्षत्रिय समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है। अभी निहाल सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पुलिस की कायराना हरकत से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। देवरिया अपराध के मामले में देश भर में ट्रेंड कर रहा। करणी सेना पुलिस को 48 घंटे का समय दे रही है। यदि 48 घंटे में विशाल के हत्यारों पर कार्रवाई नही हुई तो करणी सेना देवरिया का इतिहास बदल देगी। उन्होंने ने कहा कि पुलिस अपराधियो के पैर में नहीं सीने में गोली मारे। मुठभेड़ में पैर में गोली मारने का नाटक बंद होना चाहिए। सीएम के घर के बगल का जिला हिंसा की आग में जल सकता है।

पुलिस के लापरवाह रवैए से क्षत्रिय समाज के नौजवान मारे जा रहे हैं। विशाल के पिता ने 48 घंटे का समय दिया है। यदि निर्धारित समय में विशाल के हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना के नौजवान देवरिया पुलिस की ईंट से ईंट बजाने को विवश होंगे। इस मौके पर गोरखपुर मंडल अध्यक्ष पवन शाही सहित दर्जनों करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बुद्धस्थली रामग्राम में वैदिक मंत्रोच्चार और धम्म पाठ के साथ उत्खनन शुरू

संवाददाता–महराजगंज। भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल रामग्राम के उत्खनन का बहुप्रतिक्षित इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने पनियरा विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह व सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के साथ वैदिक मंत्रोच्चार व धम्म पाठ के साथ विशेष पूजा–अर्चन कर रामग्राम के उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर एडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा के अलावा पुरातत्व विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। रामग्राम के बारे में मान्यता है कि यहां भगवान बुद्ध के अस्थि का आठवां हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। अभी तक आठ में सात बौद्ध अस्थि स्तूप का पता लगाया जा चुका है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक आठवां अस्थि स्तूप रामग्राम में मौजूद है।

रामग्राम की प्रामणिकता अभी सामने नहीं आ पाई है। चौक जंगल में कन्हैया बाबा के टीले को लेकर मान्यता है कि यही रामग्राम है। यहां बौद्ध कालीन अवशेष भी मौजूद हैं। चीनी यात्री युवांगच्वांग द्वारा दी गई दिशा व दूरी की इस क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र पर गणना के अनुसार रामग्राम नगर की स्थिति जनपद महराजगंज के चौक कस्बे के पश्मिोत्तर स्थित कोढ़िया जंगल तथा धातु चौत्य की स्थिति चौक से 3 किलोमीटर पश्चिम धरमौली गांव के पास जंगल के बीच कन्हैया बाबा के थान नामक स्थान की ओर इंगित करती है। कन्हैया बाबा के थान पर एक विशाल स्तूप, पुष्करिणी तथा बौद्ध बिहार के खण्डहर कई एकड़ में बिखरे पड़े हैं। कोढ़ियवा जंगल में एक विशाल नगर के अवशेष भी पाये गये हैं। सांसद पंकज चौधरी पार्लियामेंट में रामग्राम व देवदह का उत्खनन कराकर बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की मांग कर चुके थे। केन्द्र सरकार ने रामग्राम व देवदह के उत्खनन के लिए केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को आदेश दे चुकी थी। भगवान बुद्ध के ननिहाल कहे जाने वाले देवदह का उत्खनन कार्य शुरू हो चुका है। रामग्राम के उत्खनन को लेकर वन विभाग की अनापत्ति का इंतजार था। जिला प्रशासन के प्रयास के बाद वन विभाग ने उत्खनन के लिए अनुमति पुरातत्व विभाग को दे दी है।

रामग्राम में उत्खन्न कार्य का शुभारंभ करते हुए केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय हुई घटनाएं भारतीय इतिहास में प्रामाणिक रूप से दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि आठवे अस्थि स्तूप के मत–मतांतर को लेकर न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में मिथकीय कथाएं प्रचलित हैं। इतिहास की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए शोध आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुई यह प्रायोगिक खुदाई हजारों वर्ष पुराने इतिहास को प्रमाणिक रूप से देखने का प्रयास मात्र है। उत्खनन मे प्रमाणित होने के बाद यह क्षेत्र बौद्ध सर्किट से जुड़ जाएगा। इससे बौद्धिस्ट टूरिज्म के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम को सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया और डॉ. परशुराम गुप्ता ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिलापंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय,नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता देवी, एडीएम पंकज वर्मा,डीएफओ निरंजन सुर्वे ,एसडीएम सदर रमेश कुमार, ईओ चौक ओमप्रकाश ,रेंजर मोहन सिंह, रेंजर ऋषभ नायक, अमरनाथ पटेल, अशोक पटेल, राजकुमार जायसवाल, अजय मद्धेशिया, पवन वर्मा, विवेक गुप्ता मौजूद रहे।

रामग्राम का उत्खनन करने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम डॉ. आफताब हुसैन के नेतृत्व में कन्हैया बाबा के टीला पर पहुंची है। खुदाई के लिए ले आउट तैयार कर निशान लगाया जा चुका है। उत्खनन के लिए टीम अपने साथ विशेष औजार लाई है। जिससे खुदाई के दौरान मिलने वाले बौद्धकालीन अवशेषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। खुदाई के दौरान मिले अवशेष को सुरक्षित रखा जाएगा। उत्खनन कार्य की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी होगी।

सरोज हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश पकड़ा गया

संवाददाता–बलरामपुर। थाना महराजगंज तराई के निबोरिया गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरोज सिंह की हत्या व लूटकांड में शामिल एक और बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास नकदी व चोरी गए कुछ कागजात मिले हैं। बदमाश की गिरफ्तारी सोमवार को बहराइच जिले के आसाम चौराहा निकट हुई है। घटना में शामिल एक बदमाश को रविवार को ही पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी थी। उसके पास घटना में प्रयुक्त कार, तमंचा व जीवित कारतूस मिले हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों बदमाश अत्यंत शातिर हैं। उनके खिलाफ कई थानों में दो–दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। एक अन्य अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी है। 12 नवंबर मध्य रात निबोरिया गांव निवासी दशरथ सिंह के घर बदमाशों ने धावा बोला था। लूट के दौरान उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरोज सिंह की हत्या कर दी गई थी। एसपी विकास कुमार ने घटना राजफाश के लिए पांच टीमें गठित की थीं। पुलिस टीम ने रविवार देर शाम जरवा कोतवाली क्षेत्र स्थित जंगल में मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाया था। जिसमें बच्छराज निवासी कोलगढ़ थाना तम्बौर जिला सीतापुर फंस गया। पुलिस का दावा है कि बच्छराज के साथ कार में दो अन्य लोग भी बैठे थे। रोकने पर कार में बैठे दो लोग भाग गए, लेकिन बच्छराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ था। पुलिस की ओर की गई फायरिंग में एक गोली बच्छराज के दाहिने पैर में लगी थी, जिससे वह घायल हो गया था। उसके पास घटना में प्रयुक्त कार, 12बोर तमंचा व जीवित कारतूस मिले थे। बच्छराज के बताने पर पुलिस ने जनपद बहराइच के आसाम चौराहा पर नाकाबंदी की। वहीं पर औरीसाईपुर थाना तम्बौर जिला सीतापुर निवासी राज कुमार पुत्र छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास पुलिस ने लगभग 15 हजार रुपए नकदी बरामद की। साथ ही चोरी गया आधार कार्ड, पैन कार्ड व बीमा सम्बन्धी कागजात पाए गए। घटना में शामिल सुल्तानापुरवा लोनियनपुरवा थाना तम्बौर जिला सीतापुर निवासी सोने लाल भी शामिल था। पुलिस का दावा है कि घटना के दौरान सरोज सिंह की नींद टूट गई थी। बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, लेकिन वह नहीं मानीं। बगल कमरे से लोगों के जागने की आवाज आने लगी। इस पर बच्छराज व सोने लाल ने मिलकर सरोज सिंह की नाक व मुंह तकिए से दबाकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मुताबिक बदमाशों ने स्वीकार किया है कि सोने चांदी के जेवरात व अल्मारी में रखा 62 हजार रुपए वे ले गए थे। बच्छराज ने राज कुमार को फोन करके गाड़ी सड़क पर लाने को कहा। राज कुमार घटना के दौरान गाड़ी चलाने का काम करता है। गाड़ी में बैठकर लोग बलरामपुर की ओर फरार हो गए। एसपी विकास कुमार का दावा है कि बदमाशों ने घटना को अंजाम तक पहुंचाने में किसी मुखविर का सहारा नहीं लिया। वे अमूमन सड़क किनारे के गांवों को ही अपना निशाना बनाते हैं। एसपी के मुताबिक राज कुमार अभी कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थनगर जेल से छूटकर आया था। उसे तराई का इलाका काफी शांत लगा था। उसने इस क्षेत्र को चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए चुना। एसपी ने बताया कि पिछले दस दिनों के बीच बदमाशों ने सिद्धार्थनगर में चोरी की तीन घटनाओं को अंजाम दिया है। वे टोल प्लाजा के सामने से अपनी गाड़ी नहीं निकलते थे। पहचान छिपाकर रखते थे। सिद्धार्थनगर जाते समय पहली बार टोल प्लाजा से बचने के लिए ही निबोरिया गांव होकर सुदर्शनजोत के रास्ते टोल प्लाजा के उस पार अपनी गाड़ी निकाली थी। पहली ही नजर में बदमाशों को दशरथ सिंह का घर भा गया था।

नेशनल कॉन्फ्रेंस में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर चर्चा

संवाददाता–बलरामपुर। एमएलके पीजी कॉलेज सभागार में सोमवार को दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स इन इनोवेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सम्मेलन का आयोजन शोध व नवाचार के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को रेखांकित करने एवं उनके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों पर विचार–विमर्श करने के उद्देश्य से किया गया। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की शुरुआत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यमों में आयोजित तकनीकी सत्रों से हुई। जिनमें विशेषज्ञ, शोधकर्ता और शिक्षाविदों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। प्रतिभागियों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा के अन्य महत्वपूर्ण आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। चौथे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता एमएलके महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ आरबी श्रीवास्तव ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता रहे डॉ राजू तिवारी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देते हुए इस क्षेत्र में जुड़े रोजगार के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने आविष्कार और खोज को परिभाषित किया। कहा कि आविष्कार वह है जिसमें आविष्कारी कदम हो। उन्होंने कॉपीराइट, जी आई, पेटेंट्स व ट्रेड मार्क के बारीकियों को स्पष्ट करते हुए इनमें जुड़े रोजगार के अवसरों की चर्चा की। तकनीकी सत्र पांचवे में मुख्य वक्ता मेजर प्रभाकर देव सिंह रहे। उन्होंने बताया कि कैसे फेक प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक है। उन्होंने बताया कि नवाचार हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। विचार ही नवाचारों को प्रेरित करते है और विकास को बढ़ावा देते है। इस अवसर पर प्रो. एम अंसारी, प्रो. वीना सिंह, प्रो. एसपी मिश्रा, डॉ शिव महेन्द्र, डॉ रामरहीस, डॉ ओपी सिंह, डॉ प्रमोद यादव, डॉ जितेन्द्र कुमार, संदीप यादव, दिनेश कुमार, अभिषेक सिंह के साथ महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण व छात्र व छात्राएं मौजूद रहे।

सभी पात्रों तक पहुंचे विकास योजनाओं का लाभ– जार्ज कुरियन

संवाददाता–श्रावस्ती। केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन एकदिवसीय भ्रमण पर सोमवार को श्रावस्ती पहुंचे। जहां विकास योजनाओं की समीक्षा की और सभी पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। निरीक्षण भवन पहुंचे केन्द्रीय मंत्री का जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ,पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया एवं मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंच कर नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की।

इसके साथ ही विकास खण्ड जमुनहा में 06 इन्डीकेटर्स पर विस्तृत चर्चा की गई है। जार्ज कुरियन ने कहा कि भारत सरकार की ओर से देश भर के चिन्हित कुल 112 जिलों में समावेशी और सर्वांगीण विकास कराया जा रहा है। केन्द्र सरकार जन–जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी है। मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेय जल, विधवा, वृद्धा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जल संचयन, कौशल विकास, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की। बैठक का संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजय कुमार यादव ने किया।

श्रावस्ती पहुंचे केन्द्रीय मंत्री जार्ज कुरियन ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र ने केन्द्रीय मंत्री से मिल कर जिले की समस्याओं को अवगत कराया। मंत्री से विकास योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में प्रशासन की मदद करने की अपील की।

बहराइच हिंसाः आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की राहत, सरकार ने दाखिल किया जवाब

संवाददाता–बहराइच। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत की है। मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगा गया जवाब दाखिल कर दिया है। याची ने इसका प्रतिउत्तर भी पेश कर दिया है। सुनवाई के समय याची का प्रति उत्तर रिकार्ड (फाइल) पर नहीं था। इस पर कोर्ट ने अपने दफ्तर को इसे रिकार्ड पर रखने का आदेश दिया। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। फिलहाल ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 27 नवंबर तक कथित अतिक्रमणकर्ताओं को राहत रहेगी। इससे पहले छह नवंबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मौखिक निर्देश दिया था। सरकार फिलहाल ऐसी कोई कारवाई न करे, जो कानून सम्मत न हो। उधर, सरकारी वकीलों ने भी कानून सम्मत करवाई करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने मामले में

राज्य सरकार को चार बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने और याची को इन पर आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। याचिका में कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्तूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हे रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या नोटिसें जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं? क्या जिन्हें नोटिसें जारी हुईं वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं? नोटिस जारीकर्ता प्राधिकारी इन्हें जारी करने को सक्षम था या नहीं। इन बिंदुओं के अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि महराजगंज बाजार की जिस सड़क पर बने निर्माणों को ढहाने की नोटिस जारी हुईं, क्या पूरा निर्माण या उसका कोई हिस्सा अवैध निर्माण था या नहीं? राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ पेश हुए और कोर्ट को वांछित जानकारी दी। बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्तूबर को हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी। इसके बाद वहां महाराजगंज के कथित अतिक्रमणकर्ताओं के निर्माणों को ढहाने की नोटिसें उन्हें जारी की गईं थीं।

खाद की समस्या को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–महराजगंज। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निचलौल क्षेत्र के किसी भी सहकारी समिति पर खाद नहीं है। इस समय खेती का काम तेजी से चल रहा है उसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। इसका लाभ प्राइवेट दुकानदार उठा रहे हैं। किसान खाद लेने के लिए गोदाम पर सुबह से कतार लगा रहे हैं। इसके बाद भी खाद नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि निचलौल क्षेत्र के सभी सहकारी समिति के गोदाम पर खाद तत्काल उपलब्ध करायें। खाद की समस्या बनी रही तो पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस मौके पर खुर्सेद मलिक, राजू भारती, दशरथ, मोइनुद्दीन अली मोहम्मद, काशी, मोहम्मदीन, महेंद्र शर्मा, कोदई, गीता देवी, रेखा देवी, सलहंती देवी ,सोमारी देवी, प्रमोद मिश्रा, राजेंद्र, अली शेर, उस्मान अली, भग्गन ,तैयब, समतुल्लाह, सुदामा, परदेसी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अयोध्या पहुंच थाईलैंड बैंकाक का एक दल, रामलला के दर्शन के साथ सरयू तट पर किया पूजन अर्चन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। थाईलैंड बैंकॉक से प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंचे 15 भक्त, हनुमत ध्यान भवन पीठाधीश्वर महंत पवन कुमार दास ऊंची खड़ाऊ वाले महाराज निर्देशन में मां सरयू के पावन तट पर सभी के कल्याण के लिए सुंदरकांड का पाठ किया और अष्टधातु से बने लॉकेट का पूजन कर जुड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। महंत पवन कुमार दास महाराज ने बताया कि थाईलैंड और बैंकॉक से 15 भक्तों का दल भारत में धार्मिक यात्रा पर पहुंच और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला का पूजन कर संतो की सेवा की।

श्री महाराज जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। सोमवार को थाईलैंड का एक दल अयोध्या पहुंच आश्रम पर पूजा अर्चना कराया गया और दूसरे सत्र में मां सरयू के पावन तट पर सभी लोक अयोध्या के संतों के साथ सुंदरकांड का पाठ जगत कल्याण के लिए किया और साथ ही साथ अष्टधातु पर अंकित बुद्ध भगवान और प्रभुश्री राम के पूजन किया गया उसके बाद जो भी भक्त धार्मिक यात्रा पर आए हैं और जो लोग इन लोगों से जुड़े हैं, सबको नाम रामनगरी में पूजित सिक्का उनके कल्याण के लिए दिया जाएगा और वह लोग अपने गले में धारण करेंगे।

अतिक्रमण हटाने गई टीम की सिपाही को जड़ा थप्पड़, पुलिस को चेतावनी देकर छत से कूदी युवती, वीडियो वायरल

संवाददाता–गोरखपुर। परसपुर के तेलहा रज्जा चौहान पुरवा में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया गया। इतना ही नहीं पुलिस को चेतावनी देकर युवती छत से कूद गई। इससे अफरातफरी मच गई। छत से कूदने के बाद चोटिल युवती को अस्पताल ले जाया गया। वहीं, लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज कराया गया है। विगत 13 नवंबर को डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर पुलिस व राजस्व टीम तेलहा रज्जा चौहान पुरवा में सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। राजस्व टीम लेखपाल अवधेश चौबे ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी रघुराज सिंह की बेटियां एकता और साधना सिंह ने परिक्रमा मार्ग से ट्राली हटाने पर विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों पर ईंट–पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। महिला कांस्टेबल मंगला सिंह यादव समेत कर्मियों ने विरोध जताया तो महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद ट्राली हटाने के विरोध की चेतावनी देकर पुलिस के सामने ही छत से कूद गई। इस दौरान स्थानीय स्तर पर अफरातफरी मच गई है। आनन–फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। अधिकारियों ने बताया कि परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज किया है। छानबीन की जा रही है।

आरोप है कि संवेदनशील मामला होने के चलते पुलिस ने पूरी घटना को दबाए रखा। वीडियो वारयल होने के बाद घटना सामने आ सकी है। इसमें युवती ने कहा कि अगर रास्ते से उसकी ट्राली हटाओगे तो वह छत से कूद जाएगी। काफी समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और कूद गई। पुलिस ने एकता को हिरासत में लिया। इतना ही नहीं ट्राली सीज की गई है। वहीं साधना पीछे से भाग निकली। वह पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाती नजर आ रही है। वहीं इंस्पेक्टर दिनेश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मिन्नतें कर रहे हैं।

सच्चे समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती –चंद्रकेतु आर्य

संवाददाता–श्रावस्ती। आर्य समाज मंदिर इकौना में भव्य वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर यज्ञ का आयोजन किया गया और लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर चलने की अपील की गई।

आर्य समाज इकौना इकौना में तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ से किया गया। सुबह यज्ञ ब्रह्म पंडित ओंकार नाथ शास्त्री की ओर से कराया गया। कार्यक्रम में यज्ञ के मुख्य यजमान चंद्रकेतु आर्य व श्रीमती राधिका सिंह , अनिल नैय्यर सपत्नी,दिनेश जायसवाल, रमेश मोदनवाल, अजय सोनी, राम सनेही, संतोष चौधरी आदि ने मिलकर आहुतियां दीं। राष्ट्रीय वैदिक भजनोपदेशक पंडित योगेश दत्त आर्य ने नित यज्ञ करो,विषयों में काहे जाए,प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले आदि भजनों से लोगों का मन मोह लिया। वहीं बहराइच की भजनोपदेशिका गीता आर्या ने अपने भजनों सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध अपना पर्यावरण कर लो। चलो आर्य समाज चलो आर्य समाज से उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्धा एवम वेदों की ओर उन्मुख होने का संदेश दिया।

दोपहर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता डा संज्ञा सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के सच्चे सुधारक थे। कार्यक्रम में राधिका सिंह, ललिता पाण्डेय, प्रभा सहित कई अन्य महिलाएं युवतियां मौजूद रहीं। सायंकालीन सभा में वैदिक भजनों प्रवचन आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विक्रम सिंह, बलराम सिंह, सुरेंद्र पाठक,राम सनेही, संतोष चौधरी, राम स्वरूप आदि कई लोग मौजूद रहे।

पुण्यतिथि पर नमन किए गए श्री महंत रामविलास दास जी महाराज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। सिद्ध पीठ संकट मोचन हनुमान किला मंदिर के संस्थापक साकेत वासी श्री महंत रामविलास दास जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि श्री महंत रामदास व महंत परशुराम दास महाराज के संयोजन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खाक चौक और संकट मोचन हनुमान किला मंदिर के महंत परशुराम दास जी महाराज ने बताया कि श्री श्री महाराज जी बाईपास पर आश्रम बनाकर के संतो असहाय व गरीबों की सेवा में तत्पर रहते थे और सेवा को ही धर्म मानते थे। हमेशा अपने शिष्यों भक्तों को सेवा का ही धर्म माननीय का उपदेश दिया करते थे। श्री महाराज जी भजन में तल्लीन रहते थे।

श्री महाराज ने बताया कि सेवा धर्म मानते थे और हमेशा शिष्यों को बताते रहते थे कि परमात्मा के मिलने का सबसे सरल रास्ता परमार्थ निस्वार्थ भाव से सेवा ही है। श्री महाराज जी बाईपास के किनारे रहते थे जो भी गरीब असहाय भूला भटका आश्रम में पहुंचा था सब की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। श्री महाराज जी के 9 वीं पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतो ने भाव रूपी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर खाकचौक मुख्य पुजारी रामचरण दास,दिगंबर, संकट मोचन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, महंत इंद्रदेव दास, वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास, सिद्ध बाबा नरसिंह दास, बड़े हनुमान के अधिकारी छविराम दास , महंत राम प्रकाश दास, महंत अवधेश दास, महंत अवध किशोर शरण, महंत राम कुमार दास,बाल योगी महंत रामदास, बालयोगी महंत विनोद दास, रामायण महंत कमला दास रामायणी , राघव दास, महंत मनीष दास, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी रमेश दास, महामंडलेश्वर महंत गिरिश दास,श्रीराम कथा के मर्मज्ञ चंद्रांशु महाराज, महंत दामोदर दास, राजभूषण दास रामायणी,महंत विजय रामदास, अमर सिंह, विनोद सिंह, डॉ एमपी यादव , पार्षद अंकित त्रिपाठी श्री चंद्र यादव सहित सैकड़ो संतो महंतों श्रद्धांजलि अर्पित की।

सम्मानित किए गए किसान, भूतपूर्व सैनिक और संभ्रान्त लोग

संवाददाता—संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में हैंसर बाजार धनघटा नगर पंचायत के मानसिंह बाग में आयोजित द्वाबा महोत्सव में जनपद के प्रगतिशील किसान, भूतपूर्व सैनिक, शहीदों के परिवार और संभ्रान्त लोगों को सम्मानित किया गया। एसडीएम धनघटा अरुण कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष रिन्कू मणि और पूर्व विधान सभा प्रत्याशी नीलमणि ने सभी को प्रशस्ति पत्र, मोमेन्टो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में नीलमणि ने कहा कि आज मुझे आम सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला। इससे मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। द्वाबा महोत्सव का आयोजन अब प्रत्येक वर्ष होगा। सम्मानित होने वालों में रंजीत पटेल, रामरूप मौर्य, राजकुमार राय, लालजी सुरैना, सुरेन्द्र पाठक, चन्द्र प्रकाश शुक्ल, इन्द्रेश कुमार, चन्द्रभान यादव, शिवनन्द शर्मा, अनुराग राय, लालजी यादव, चन्द्रकान्त मणि, राजनारायण राय, विजय प्रताप सिंह, बलवीर यादव, गोविन्द चतुर्वेदी, सचिदानंद पांडेय, पवन कुमार राय, रमेश राय, ओम प्रकाश मौर्य, राम सिंह मौर्य, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अनुपम पांडेय, देव प्रसाद मौर्य, सदानन्द त्रिपाठी, निलेश मिश्र, श्यामजी उपाध्याय, सुरेश त्रिपाठी, विनोद कुमार, रामरतन यादव, घनश्याम, अमर सिंह, संत कुमार सिंह, घरभरन चौधरी, अरुण सिंह, जगदीश नारायण पांडेय, रामानंद कन्नौजिया, विजयसेन पाल, भानुप्रताप सिंह, भानु प्रताप चतुर्वेदी, रणवीर पाल, विजय कुमार उपाध्याय, जय प्रकाश राय, प्रमोद कुमार, रुद्रनाथ चतुर्वेदी, केशरीनंदन शामिल रहे।

श्रीराम जी का तिलकोत्सवः वैदिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ कार्यक्रम, शामिल हुए नेपाल के राज्य के मुख्यमंत्री

संवाददाता—अयोध्या। अयोध्या के रामसेवकपुरम में आयोजित भगवान श्रीराम का तिलकोत्सव कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्पन्न कराया गया। उत्सव में वर पक्ष से अयोध्या के मेयर और वधू पक्ष से जनकपुर से नेपाल के मधेश राज्य के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने छह कैबिनेट मंत्रियों के साथ शामिल हुए। वैदिक रीति रिवाज के साथ तिलकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान लग्न पत्रिका सौंपी गई।

उत्सव में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महाराजा दशरथ की भूमिका निभाई। इस दौरान महिलाओं ने तिलकोत्सव का गीत गाया।

किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन पर बरसी भाकियू

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। इटवा तहसील परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें भाकियू के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन पर खूब बरसे। पंचायत के अंत में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्री ज्ञापन एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य को सौंपकर तय समय में निदान कराने की मांग की। भाकियू के तहसील अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर प्रशासन के जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे महंगाई के इस आलम में किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों से उर्वरक गायब है। धान की सरकारी खरीद केवल कागजों में हो रही है। किसानों के हक की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। नहरें व नलकूप भी खस्ताहाल हैं। गांवों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। संगठन अब चुप रहने वाला नहीं है। किसानों से जुड़ी इन समस्याओं का अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन इसके लिए आन्दोलन करेगा। इस मौके पर मोहम्मद मुनीफ खान, हरिश्चन्द्र विश्वकर्मा, कंचन देवी, राम लखन, पुजारी, विन्ध्याचल, भगवत विश्वकर्मा, राजकुमार, पप्पू सोनी, मेंहदी हसन, जगदीश आदि मौजूद रहे।

प्राकृतिक चिकित्सा से बीमारियों का इलाज संभव — सन्नो दूबे

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती।आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आयुष विभाग के हेल्थ वेलनेस सेंटर शंकरपुर की योग प्रशिक्षिका योगाचार्या सन्नो दुबे ने इस अवसर पर महिला महा विद्यालय में छात्राओं को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांतों और लाभों के बारे में शिक्षित करने के इरादे से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न विधियां आहार चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, वायु चिकित्सा, क्षेत्रीय वनौषधियां का बिना दुष्प्रभाव प्रयोग होता है, जिसमें मुख्य उपचार मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का स्नान, सूर्य स्नान, गर्म और ठंडा सेक, कटी स्नान, मेहन स्नान, पैर—हाथ का गर्म सेंक, वाष्प स्नान, पूर्ण टब स्नान, रीढ़ स्नान सर्वांग गीली चादर लपेट, छाती की पट्टी, व घुटने की पट्टी, एनिमा, जलनेती, वमन, माथे की पट्टी, पेट की पट्टी रोगानुसार मालिश की क्रियाएं के बारे में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी छात्राओं को यह सन्देश दिया की यह सरल सहज, उपचार की प्रक्रिया है, जिसे हमें जीवन में अपनानी चाहिए।

महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो सुनीता तिवारी ने कहा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ उपलब्ध कराए हैं प्रकृति के भंडार मे हर गुण हर रहस्य छिपे है । आयुर्वेद और योग को हमें अपने जीवन शैली में उतरना चाहिए तभी हम स्वस्थ बने रहेंगे। शारीरिक शिक्षा विषय की सहायक आचार्य डॉ संतोष यदुवंशी ने कहा कि आयुर्वेद के गर्भ में हर समस्या का समाधान है। प्रकृति अगर हमें समस्या देता है कि तो उसके समाधान का भी उपाय देता है। प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे उतना ही सुख के करीब रहेंगे।कार्यक्रम में काजल, रूप, विदुषी, शशि, रितिका,रेनू, एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित था।

मुंबई के कलाकारों ने नृत्य कला से दिखाई झांकियां

संवाददाता—संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में हैंसर बाजार धनघटा नगर पंचायत के मानसिंह बाग में आयोजित द्वाबा महोत्सव में मुम्बई से आए कलाकारों की टीम ने द्वाबा महोत्सव के मंच पर कई हैरत अंगेज कारनामें प्रस्तुत किए। नृत्य कला से झांकियां दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने मुम्बई से आए कलाकारों ने एक पतले पिलर पर खड़े होकर करतब दिखाया तो हर कोई झूम उठा। कालीदह लीला व क्षीर सागर में शेष शैय्या पर सोये विष्णु भगवान की झांकी व भारत माता की झांकी के साथ ही कई अलग—अलग कला का प्रदर्शन किया। इनकी प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहीं। परिसर में मौजूद दर्शक पूरे समय तक तालियां बजाते रहे।

आपत्तियों का स्थलीय सत्यापन करेगी तहसील स्तरीय टीम

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची में बोर्ड परीक्षा के लिए 92 केंद्र ही बनाए गए हैं। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने या संशोधन के लिए 88 कॉलेजों ने प्रत्यावेदन और आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें अधिकांश परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। अब प्रस्तावित के साथ ही आपत्ति दाखिल करने वाले कॉलेजों की पुनरू स्थलीय जांच तहसील स्तरीय जांच टीम करेगी। टीम को 23 नवंबर तक जांच रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष सौंपनी होगी। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र बनने या निरस्त करने पर अंतिम मुहर लगेगी। जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन 221 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें 28 राजकीय, 48 अशासकीय व 155 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 92 केंद्रों की अनंतिम सूची जारी की गई है। इस पर आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम तिथि तक 88 आपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद उसका निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय कमेटी करेगी। स्थलीय जांच में बोर्ड की ओर से प्रस्तावित 92 कॉलेजों की भी पुनरू सत्यापन किया जाएगा। उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में संबंधित तहसील के तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानार्गय शामिल हैं। यह जांच टीम 23 नवंबर तक रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के समक्ष सौंपेगी। इसके बाद सूचनाएं बोर्ड को भेज दी जाएगी। फिर से वहां से अंतिम सूची जारी की जाएगी। इनमें अधिकांश ने केंद्र बनाने या संशोधन करने के लिए प्रत्यावेदन या आपत्ति दी गई है। बोर्ड की परीक्षा 2025 में इन केंद्रों पर 64910 छात्र—छात्राएं परीक्षा देंगे, इसमें हाईस्कूल के 35951 और इंटर के 28959 छात्र—छात्राएं शामिल हैं। वहीं, बोर्ड परीक्षा 2024 में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 60350 छात्र—छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस बार 4560 छात्र—छात्राएं अधिक हैं। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इस बार 4560 परीक्षार्थी अधिक हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन 92 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची पर आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम तिथि तक 88 आपत्ति आई है। परीक्षा केंद्रों एवं छात्र आवंटन में किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत की जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित जांच टीम स्थलीय सत्यापन करेगी। प्रस्तावित के साथ ही आपत्ति देने वाले कॉलेजों का स्थलीय सत्यापन होगा। टीम को 23 नवंबर तक रिपोर्ट देनी है।

सड़क हादसे में दो की मौत चार घायल

संवाददाता—अयोध्या। ट्रक और कार में हुई टक्कर के चलते भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में दो मासूम बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रविवार की रात करीब 2 बजे कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर के पास प्रयागराज हाईवे पर हुआ बताया जाता है। कार सवार सभी लोग एक ही परिवार के तथा आपस में रिश्तेदार हैं। सभी लोग कार से किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी गए थे वहां से रविवार की रात में गोंडा वापस जा रहे थे। रात करीब 2 बजे जैसे ही बीकापुर

कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास पहुंचे ट्रक की चपेट में कार आ गई।

कोतवाली पुलिस द्वारा करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर लाया गया। जांच पड़ताल के बाद इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक धर्मेंद्र रंजन ने अरविंद गुप्ता उर्फ राजेंद्र गुप्ता 45 निवासी गोंडा बस स्टैंड एवं राकेश गुप्ता 42 बस निवासी रोजारपुर जनपद बलरामपुर को मृत घोषित कर दिया। जबकि हादसे में घायल नानपारा बहराइच निवासी आशीष गुप्ता 32 वर्ष, गोंडा बस स्टैंड निवासी रंजना गुप्ता 35 वर्ष, सुरभा 5 वर्ष पुत्री अरविंद गुप्ता, श्रुति 6 वर्ष पुत्री अरविंद गुप्ता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के आने के बाद सोमवार सुबह कोतवाली पुलिस द्वारा मृतकों के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। दुर्घटना करने वाली ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

शुरु हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का काम, अब प्रति यूनिट होगा हिसाब

संवाददाता—अंबेडकरनगर। बिजली चोरी रोकने व प्रत्येक यूनिट खपत का हिसाब रखने के लिए पावर कारपोरेशन का 30 हजार ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाने काम शुरू हुआ गया है। अब तक 50 ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आगामी तीन माह में सभी ट्रांसफार्मर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जाएगा। तीन चरणों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है। पहले चरण में फीडर, दूसरे चरण में ट्रांसफार्मर व तीसरे चरण में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिले में 41 उपकेंद्र हैं यहां 156 फीडर संचालित हैं, इनसे जुड़े चार लाख 25 हजार उपभोक्ता हैं। टांडा, अकबरपुर, सेनपुर, अशरफपुर बरवां, आलापुर, जलालपुर, मालीपुर, भीटी उपकेंद्र के 64 फीडर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। पावर कारपोरेशन बिजली चोरी रोकने के लिए अलर्ट है। हालांकि कुछ दिन पहले उपभोक्ताओं के विरोध पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। पावर कारपोरेशन स्मार्ट मीटर के फायदे बताने के लिए बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूक कर रहा है। जिले के चार लाख 25 हजार उपभोक्ताओं के घर पर ट्रांसफार्मर तथा फीडर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन ने सरयू स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। संस्था 500 घरों में स्मार्ट मीटर लगा चुकी है। कंपनी के प्रभारी रौशन प्रभात ने बताया फीडर तथा 25 केवीए के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ है। घर व दुकान में भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर तथा फीडर एवं उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद गलत बिल से निजात मिलेगी। उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल मीटर रीडर का काम खत्म हो जाएगा। उपभोक्ता मीटर से बाईपास चलाएंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। मीटर में लगा चिप भी ब्लाक होने की संभावना रहेगी।

महंगे रेट पर बिक रही यूरिया व डीएपी, जिम्मेदार बेखबर

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। क्षेत्र की सहकारी समितियों पर खाद की कमी का फायदा बाजार के निजी दुकानदार जमकर उठा रहे हैं। प्राइवेट दुकानों पर यूरिया का रेट तीन सौ रुपये पार कर गया है जबकि डीएपी 16 सौ रुपये तक प्रति बोरी बिक रही है ओर लोग महंगे रेट पर खाद खरीदने को विवश हैं। वहीं जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं।

डुमरियागंज क्षेत्र के कई स्थानों पर स्थित सहकारी समितियों पर इन दिनों खाद नदारद है। इससे यूरिया खाद की 45 किलो वाली बोरी 300 रुपये से अधिक दर पर बेची जा रही है। जबकि सरकारी समितियों पर यही खाद की बोरी 270 रुपये में मिल रही है। वही डीएपी 1500 से 1600 रुपये में बिक रही है। हालांकि समितियों पर खाद समय—समय पर पहुंच रही है पर वह बहुत कम रह रही है। इससे अधिकतर किसान समितियों से बिना खाद के ही लौट जा रहे हैं। क्षेत्र के किसान अमरनाथ पाण्डेय, राम अचल यादव, ऐस मोहम्मद, विक्रम आदि का कहना है कि सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिल पा रही है। चक्कर काटने के बाद पता चलता है कि खाद आने वाली है जब बटती है तो अधिक भीड़ लगने से कुछ लोगों देकर बंद कर दिया जाता है। गरीब किसान वंचित होकर निजी दुकानों से महंगी खाद खरीदकर अपने खेतों में डालने को मजबूर होता है।

उन्होंने कहा कि सरकारी रेट पर खाद मिलने से खेती में कम लागत आती है। जब बाजार से महंगे दाम की खाद खरीदकर डाली जाएगी तो किसानों को अच्छा लाभ मिलना मुश्किल है। उन्होंने सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध कराने व कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने की मांग है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0—500/2023
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला—बस्ती

चन्द्र कुमार आदि
बनाम
जवाहर लाल आदि

1. जवाहर लाल उम्र लगभग 51 साल पुत्र जगन्नाथ निवासी मौजा पिकौरा तप्पा पिलाई परगना नगर पूरब तहसील व जिला—बस्ती
—प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. दीपक कुमार उम्र लगभग 34 साल पुत्र स्व0 रामयज्ञ निवासी मौजा बेलवाडाड तप्पा पिलाई परगना नगर पूरब तहसील व जिला—बस्ती
—प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 02—12—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 12 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0—272/2020
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला—बस्ती

श्रीमती रकीबुन्निशा
बनाम
श्रीमती अजमेरून्निशा

1. श्रीमती अजमेरून्निशा उम्र 40 वर्ष पुत्री अमीरूल्लाह बेवा शाबिर अली निवासी ग्राम अमौली तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती हाल मुकाम मौजा महसो तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील बस्ती पोस्ट महसो जिला—बस्ती

तारीख पेशी 17—01—2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 17 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

शादी का जश्नः जाम में फंसे लोगों का मन घबराया, जब डीजे वाले ने जोर से बजाया 'लाल घाघरा'

संवाददाता—गोरखपुर। बरात में डीजे के कानफोड़ू आवाज और लाल घाघरा जैसे फूहड़ गानों के बीच बराती रविवार रात को नाचते—झूमते निकले तो सड़कों पर जाम लग गया। डीजे के तेज आवाज के चलते जाम में फंसे लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब आतिशबाजी शुरू हुई। डीजे से उनकी धड़कनें तेज हो गईं और पटाखों के धुएं से सांसें फूलने लगीं। जाम में फंसे लोगों की परवाह किए बगैर सड़कों पर कब्जा कर बरात जाती रही और जाम में फंसे लोग कहते सुने गए...कोई तो इन्हें रोके। इस सहालग में सबसे ज्यादा शादियां थीं। डीजे के शोर को रोकने और सड़क पर जाम न लगने पाए, इसके लिए पुलिस—प्रशासन ने मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक कर गाइडलाइन बताया था, लेकिन जब शादियों के लिए बरात निकली तो सारे—नियम कानून लोग भूल गए। रात करीब 10 बजे अलहदादपुर में एक बरात जा रही थी। डीजे पर बड़े—बड़े साउंड बॉक्स लगे थे, उसके पीछे बराती थे। बैंडबाजा को छोड़ बराती डीजे पर बज रहे लाल घाघरा जैसे गानों पर नाचने—झूमने लगे। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि बरात के पीछे जाम में फंसे श्रीनिवास ने अपने कान बंद कर लिए। कई गाड़ियों के चालक लगातार हॉर्न बजाते रहे, लेकिन डीजे की कानफोड़ू आवाज के आगे उनकी आवाज दबकर रह गई। उसमें डीजे तो नहीं था, लेकिन बैंडबाजे पर नाचते हुए बरातियों ने जाम लगा दिया। चौराहे से निकलने में आम लोगों को 10 से 15 मिनट लग गए। इसी तरह सूबा बाजार में एक बरात जा रही थी। पीछे बैंडबाजा और डीजे पर बराती थिरकने में व्यस्त थे। पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी तरह किनारे होकर लोग उसमें से निकले।नौसड़ और बाघागाड़ा के पास लंबा जामरु रविवार की शाम करीब सात बजे बाघागाड़ा के पास लंबा जाम लग गया। यहां दो बरात निकली और कुछ देर तक सड़क पर बरातियों ने कब्जा जमा लिया। जाम में फंसे लोग परेशान हो गए। करीब आधे घंटे बाद रुक—रुक कर गाड़ियां रेंगने लगी तो तब जाकर जाम हट पाया। देर रात बरात की वजह से नौसड़ के पास भी लंबा जाम लग गया। पुलिस पहुंची, लेकिन भीड़ के आगे बेबस नजर आई।

कार्यालय ग्राम पंचायत रोझिंया
विकास खण्ड बहादुरपुर जनपद-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज—2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई—रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोड़ा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेंटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता निविदा दिनांकः 19.11. 2024 से 24.11.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 25. 11.2024 दिन में 02:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनांक नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः— निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-राजमनि	सचिव- रवि प्रकाश पाण्डेय
ग्राम पंचायत-रोझिंया	ग्राम पंचायत-रोझिंया
विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /18.11.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com